bjpkamaljyoti@gmail.com / www.up.bjp.org
संवत 2078 युगाब्द 5123 कुल पृष्ठ –34 अंक – 14

वर्तमान कमल ज्योति

लोक जागरण अंक

₹10

MADHUR
बेहतर सुरक्षा
कानून व्यवस्था में सुधार

जनसभा

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email- bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

"हर हर महादेव"

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

लोकतन्त्र का महापर्व

सम्पादकीय

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव हो रहे है।

आज विशाल देश मे लोक तन्त्र भी खतरे में है? राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नही रह गया है, अधिकांश दल परिवार वादी दल हो गये है। राजनीति को वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदाय वाद, आतंकवाद प्रभावित कर रहा है। राजनीतिक दल सपा, बसपा, कांग्रेस झूठे वादे प्रलोभन दे रहे है। वही भाजपा राष्ट्रीय दृष्टिकोण लेकर इस चुनाव में उतरी है।

पहले देश के हित के लिए उपयोगी देखकर ही अपना मत डाले जाते थे। मतदान हमारा अधिकार है और मतदान करना हमारा कर्तव्य है। राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो मतदाता को भ्रष्ट करके मतदान की प्रक्रिया को भ्रष्ट न करें। निर्वाचन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। वो भी निष्पक्ष, स्वस्थ चुनाव के लिए प्रयास करता है। विशेष कर युवा को तो निश्चित रूप से ही मतदान करना चाहिए क्योंकि युवा देश की नींव होते है और वह अच्छी परख भी रखते है। मतदाता को निडर होकर देशहित में मतदान करना चाहिए। मतदाता चुनाव में एक नायक होता है। आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और मतदान का महत्व बताने के लिए मतदान जागरूकता अभियान भी चलाया है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन–व्यवस्था का नाम है, जिसमें जनता के हित के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सारी व्यवस्था का संचालन किया करते हैं। कई देशों में इस प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, राजनीतिक शब्दावली में उन्हें लोक–कल्याणकारी राज्य और सरकार कहा जाता है। यदि लोक या जनता द्वारा निर्वाचित सरकार लोक–कल्याण के कार्य नहीं करती, तो उसे अधिक से अधिक पांच वर्षों के बाद बदला भी जा सकता है। पांच वर्षों में एक बार चुनाव कराना लोकतंत्र की पहली और आवश्यक शर्त है। चुनाव में प्रत्येक बालिग अपनी इच्छानुसार अपने मत (वोट) का प्रयोग करके इच्छित व्यक्ति को जिता और अनिच्छित को पराजित करके सत्ता से हटा सकते है। भारत में **"नोटा"** की भी व्यवस्था है। इस प्रकार लोकतंत्र में मतदान और चुनाव का अधिकार होने के कारण प्रत्येक नागरिक परोक्ष रूप से सत्ता और शासन के संचालन में भागीदारी है। लोकतंत्र में अब प्रायः सारी राजनीतिक गतिविधियों वोटों के गणित पर ही आधारित होकर संचालित होनी है। लोक–हित की बात पीछे छूट जाती है। अक्सर चतुर–चालाक राजनीतिज्ञ जनता का मत चुनाव के अवसर पर पाने के लिए अनेक प्रकार के सब्जबाग, प्रलोभन, झूंठ का सहारा लेते हैं। अब यह मतदाता पर निर्भर करता है कि वह उनके सफेद झांसे में आता है कि नहीं, फिर भी निश्चय ही आज का मतदाता बड़ा ही जागरुक, सजग और सावधान है। वह लोतंत्र और चुनाव दोनों का अर्थ और महत्व भली प्रकार समझता है। चुनाव के समय की घोषणाओं को ही उसे सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि नीर–क्षीर विवेक से काम लेकर उपयुक्त, ईमानदार और जन–हित के लिए प्रतिबद्ध दल के पक्ष में ही मतदान करना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में वास्तविक लोकतंत्र की रक्षा संभव हो सकती है। चुनाव, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त और सफलता की कसौटी है, अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसके प्रति सावधान हो निश्चित मतदान करें। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यह सोचकर चुनावों के समय मत का प्रयोग नहीं भी करते कि हमारे एक मत के न डलने से क्या बनने–बिगड़ने वाला है? पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं। कई बार हार–जीत का निर्णय केवल एक ही वोट पर निर्भर हुआ। वर्तमान समय में अच्छे योग्य प्रत्याशी दल को अगर हम चुनकर नहीं भेजते हैं तो जिस समग्र विकास, सुख, शान्ति, समृद्धि की हम संकल्पना करते हैं। वह अधूरी रह जायेगी। इस देश में योगी–मोदी जी की सरकार प्रमाणिकता के साथ एकात्म मानववाद **"अन्त्योदय"** के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है। उसमें स्वस्थ लोकतंत्र की गारन्टी है। आइये मतदान अवश्य करें।

akatri.t@gmail.com

भाजपा सरकार का मतलब है, गरीब कल्याण के लिए निरन्तर काम : नरेन्द्र मोदी

सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और विकास के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने का निर्णय यूपी की जनता ने काफी पहले ही कर लिया है। ऋषियों मुनियों की तपस्थली सीतापुर व यहां की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के होने का मतलब है दंगाराज, माफियाराज और गुंडाराज पर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा–पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहन–बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है– गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है– केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम।

डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन–रात काम कर रही है। यूपी का विकास वे लोग नहीं कर सकते जो दंगाइयों, गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देते हों। इसलिए जनता कह रही है – जो कानून का राज लाए हैं, हम उनको लाएंगे।

कहा कि आज पूज्य संत रविदास जी की जयंती भी है। आज दिल्ली में उनके मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदास जी राजस्थान जा रहे थे, तब दिल्ली में उन्होंने उसी स्थान पर विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं, जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य मेरे माध्यम से हुआ। 2017 से पहले जिन लोगों ने पांच वर्ष सरकार चलाई, उन्हें संत रविदास जी से चिढ़ रही जबकि संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों का कल्याण है। गरीब महिलाओं को खुले में शौच के अपमान से, पीड़ा से मुक्ति चाहिए थी। भाजपा सरकार ने यूपी में दो करोड़ से ज्यादा इज्जत घरों का– शौचालयों का निर्माण करके उनके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी दूर की।

मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जहाँ सभी को अन्न मिले, समाज समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को दो वर्ष से निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक–एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। हर समुदाय, हर वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जब गरीब की तकलीफ का अहसास हो तो ऐसे ही काम किया जाता है। पूरे कोरोना काल में मेरा एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित रहा, किसी गरीब के घर ऐसा दिन नहीं आये कि उसे भूखा सोना पड़े, इसके लिए हम गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आये। गरीब किसी वर्ग का हो, वह जानता है कि संकट के समय किसने साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को गैस का

कनेक्शन दिया, उनकी परेशानी दूर की। प्रधानमंत्री बदला, सोच बदल गई। आजादी के 70 साल बाद भी लोग शुद्ध पीने के पानी के लिए परेशान थे। महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। हमने नल से जल का बड़ा अभियान चलाया है। हम हर घर में पानी पहुंचाने की चिंता कर रहे हैं।

कोरोना के समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी सरकार ने ध्यान रखा। पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम गांवों तक पहुंचता ही नहीं था। वर्षों कार्यक्रम चलते थे, गरीबों को वैक्सीन की एक डोज नहीं लग पाती थी। आज भाजपा सरकार है, देश के कोने–कोने में गरीब को निःशुल्क वैक्सीन लगवा रही है। विदेशों में कोरोना का ही टीका बहुत अधिक कीमत पर लग रहा है जबकि हम अपने नागरिकों बिलकुल फ्री ऑफ़ कॉस्ट टीका उपलब्ध कराया क्योंकि हमें आपकी चिंता है। कोरोना में गरीबों को आयुष्मान योजना का भी लाभ मिला। मैं गरीबी जीकर आया हूं। हमने योजना लाकर पांच लाख रुपये तक की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि कोई गरीब परिवार इलाज के अभाव में दम न तोड़े। आखिर सरकार होती किसके लिए है। सरकार गरीबों के लिए ही होती है। डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। हमारे गरीब, पिछड़ों का सपना था कि उनके पास भी पक्का घर हो। भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष में केवल यूपी में 34 लाख पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। जिन्हें नहीं मिला है, उन्हें भी मिल कर रहेगा। मोदी है, करके रहेगा, देकर रहेगा। इस बार के बजट में एक साल में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आज पूज्य संत रविदास जी की जयंती है। 2017 से पहले जिन लोगों ने पांच वर्ष सरकार चलाई, उन्हें संत रविदास जी से चिढ़ रही जबकि संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है।

यूपी में तो पारंपरिक लघु व कुटीर उद्योग बहुत हैं। आज मुझे भी दरी का तोहफा मिल गया। बड़े–बड़े शहरों के नाम सुने थे, सीतापुर का नाम बहुत सुना था। मेरे गांव में जब मैं छोटा था, सीतापुर का नाम सुनता था। लोगों को आंख की कोई बीमारी होती थी तो सीतापुर आते थे। सीतापुर के बुनकर भाइयों का परिश्रम दुनिया भर में दिखे, इसके लिए हम वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) लेकर आए हैं। देश के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं, उनके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। लोकल फॉर वोकल अभियान से सीतापुर की दरी बिकने लगी तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मैं आपके लिए बोलता हूं। वे लोग यहां के कारीगरों के बजाय विदेश से खरीद लाते थे।

आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार सभी देशवासियों को है। जब कानून का राज नहीं होगा तो गरीब को ही पिसना होगा। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो घोर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी–कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। आए दिन व्यापारियों से लूट होती थी। 2017 से पहले खनन माफिया और भू माफिया का राज चलता था। अब योगी जी की सरकार यूपी के नागरिकों को इन दंगाइयों, माफियाओं और अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है – जो कानून का राज लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी का विकास वे लोग नहीं कर सकते जो दंगाइयों, गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देते हों। उत्तर प्रदेश के जागरुक लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। दंगावादी लोग यूपी के लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको एकजुट रहना है। याद रखिए – पहले मतदान, कमल निशान, फिर दूसरा कोई काम।

सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिल के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थीं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड चीनी मिलों को बंद करने का भी रहा है। योगी सरकार नई चीनी फैक्ट्रियां भी लगा रही हैं और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। हम एथेनॉल पर जोर दे रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। देश में अधिक से अधिक उत्पादन, रोजगार के अवसर बने हैं। पहले मोबाइल कितने महंगे होते थे। विदेश से मोबाइल आते थे। भाजपा सरकार की कोशिश से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। मोबाइल, इंटरनेट सस्ता हुआ है। नीयत साफ हो, प्रयास ईमानदार हो, दिल में सेवा का भाव हो तो रास्ते निकलते ही हैं। एलईडी बल्ब छह वर्ष पहले 300 से 400 रुपये में आता था। हमने देश में उत्पादन पर जोर दिया, आज यह 50 से 60 रुपये में मिल रहा है। बिजली बिल भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर भी खोला गया है, इससे भी रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी अभूतपूर्व प्रयास किए गए। 2007 से 2017 तक दो लाख से भी कम सरकारी नौकरियां यूपी के युवाओं को मिलीं जबकि योगी सरकार ने पांच वर्ष में साढ़े चार लाख नौकरियां दीं। घोर परिवारवादियों की सरकार में नौकरियां कैसे मिलती थीं, यह यूपी की जनता जानती है। नैमिषारण्य के विकास के लिए योगी सरकार ने काम किया है वरना, नैमिषारण्य को लेकर घोर परिवारवादियों का रवैया कैसा था, आप मुझसे अधिक जानते हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की सुख, शांति और खुशहाली के लिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइये। ■

विकसित यूपी का सपना- जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के कस्ता, धौरहरा (लखीमपुर खीरी) और कुर्सी (बाराबंकी) में आयोजित जन–सभाओं को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश की जनता से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का विकास कभी नहीं कर सकती। ये केवल और केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का विकास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ही कर सकती है। यूपी में एक ओर जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास को घर–घर पहुंचाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार है। भाजपा परिवारवाद को नकार कर एक–एक कार्यकर्ता को उनकी मेधा के आधार पर आगे बढ़ाती है। भाजपा ही एक एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण परिवार से आये श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं एक अदना सा पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अन्य पार्टियों में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां परिवारवाद हावी है। यूपी की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को सदा के लिए तिलांजलि देने के मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार फिर भाजपा 300 पार।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ही दूसरा नाम करप्शन, कमीशन और क्राइम है। सपा हो और अपराधी न हो तो सपा का कार्यकर्ता कैसे होगा! इनके कार्यकर्ताओं का अभी भी वही धौंस है। कहते हैं कि 10 मार्च को देख लेंगे। वही धमकी। रस्सी जल गयी, पर बल अभी तक नहीं गया है। अखिलेश यादव सरकार ने 16,000 करोड़ रुपये का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था। ये सर्टिफिकेट देते कैसे क्योंकि इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार किया था। सपा–बसपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाराज को बढ़ावा दिया, गुंडों का आतंक कायम होने दिया जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुंडाराज और माफियाराज का सफाया किया। आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं लेकिन अभी भी यूपी को गुंडाराज और माफियाराज की ओर धकेलने वाले लोग इन्हें जेल से ही चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे लोग यूपी को फिर दंगों की आग में झुलसायेंगे। सपा के आधे प्रत्याशी जेल में हैं तो आधे बेल पर। यही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए प्रभु श्रीराम के भक्त कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, आज ये लोग मंदिर–मंदिर घूम रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।

हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और रोजगार युक्त प्रदेश बनाना है। हम ऐसा यूपी बनाना चाहते हैं जहाँ किसान खुशहाल हों, छात्रों को उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हो और महिलायें सशक्त हों। हम यूपी में औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हैं, हम स्वस्थ और विकसित यूपी का सपना लेकर चले हैं।

आज पुलवामा हमले की तीसरी पुण्यतिथि है। हम अपने वीर जवानों को भावविभोर श्रद्धांजलि देते हैं लेकिन हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयरस्ट्राइक करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

आदरणीय भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला जन–धन खाताधारकों के एकाउंट में तीन किस्तों में 1,500 रुपये पहुंचाए। हमारी सरकार ने देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों के जीवन में उत्थान लाने का कार्य

किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख घर बने हैं, जिसमें गैस कनेक्शन, बिजली, पानी और शौचालय का प्रबंध किया गया है। लखीमपुर में भी लगभग एक लाख आवास बनाए गए हैं। साथ ही, देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया गया। हमारी सरकार ने विकास को जन–जन तक पहुंचाया है। यह किसी जाति या धर्म को देख कर नहीं किया गया। यदि सड़कें बनाई गई तो सबके लिए, बिजली पहुंचाई गई तो हर घर में, जन–धन एकाउंट खोला गया तो सबके खोले गए, गैस कनेक्शन दिया गया तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को उपलब्ध कराया गया। उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड़ इज्जत घर बनाए गए। सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई। कोरोना काल में देश के हर नागरिक के दो वक्त की रोटी की चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश में भी लगभग 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दी और एससी–एसटी भाइयों के अधिकारों में कोई कटौती किये बिना आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को भी 10% का आरक्षण दिया। यूपी में हमारी सरकार में दो एम्स, एक आयुष यूनिवर्सिटी और दो और मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। पिछले पांच वर्षों में यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 से 59 तक पहुंचाई गई। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। पांच एक्सप्रेस–वे बन रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इकॉनोमिक कॉरिडोर बन रहा है। इस बार के बजट में 25,000 किमी राजमार्ग और बनाए जायेंगे। केन–बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इस परियोजना के लिए इस बार के बजट में लगभग 44,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से 13 जिलों में पानी की समस्या खत्म हो जायेगी और लगभग 62 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। यूपी में विगत पांच वर्षों में 10 नए विश्वविद्यालय, 77 कॉलेज और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। लखीमपुर खीरी में भी आईटीआई कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और देवकीनाथ में मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। धौरहरा के लोकसभा क्षेत्र में 296 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए की स्वीकृति मिल गई है। इस पर लगभग 36.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां इलेक्टीकसिटी के पांच पावर स्टेशन स्वीकृत हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। गोला से लेकर शाहजहांपुर तक नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। मतलब, हर जगह विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।

हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और रोजगार युक्त प्रदेश बनाना है। हम ऐसा यूपी बनाना चाहते हैं जहाँ किसान खुशहाल हों, छात्रों को उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हो और महिलायें सशक्त हों। हम यूपी में औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हैं, हम स्वस्थ और विकसित यूपी का सपना लेकर चले हैं। आज उत्तर प्रदेश में माफिया या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर या फिर सपा के साथ। हमने मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर एवं बहराइच में एंटी–टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। सपा की अखिलेश सरकार में सैकड़ों दंगे हुए जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। यूपी की जनता आज भी मुजफ्फरनगर के दंगों का दर्द महसूस कर रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अखिलेश सरकार इसके लिए दोषी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ग विशेष को राहत पहुंचाने के लिए भी अखिलेश सरकार को फटकार लगाई थी। कैराना से भी कई परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज वे फिर अपने घरों में वापस आकर सम्मान के साथ रह रहे हैं क्योंकि आज यूपी में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार है।

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मैं बार–बार अखिलेश यादव से सवाल कर रहा हूँ कि आपने मुख्यमंत्री रहते गोरखपुर सीरियल बम ब्लास्ट और रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमलों के गुनाहगार आतंकियों को बचाने का प्रयास क्यों किया था लेकिन वे इस पर कुछ भी नहीं बोलते। अखिलेश यादव जी, आपकी चुप्पी ही आपकी सच्चाई बताती है कि आपका उद्देश्य क्या है। अखिलेश यादव ने कहा था कि सामजिक सद्भाव के लिए उन्होंने इन आतंकियों पर से केस हटाये हैं। ये कैसा सामाजिक सद्भाव है जो देश की सुरक्षा से भी ऊपर है! मतलब स्पष्ट है कि सपा की नीयत ही गुंडों, माफियाओं और आतंकियों को संरक्षण देना है। ये तो अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव द्वारा आतंकियों को बचाने के प्रयास को अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत में सुनवाई के बाद लश्कर के आतंकियों को फांसी और उम्र कैद की सजा हुई। आतंकियों को बचाने वाले यूपी का भला कभी नहीं कर सकते। आप तो किसान हो, आप तो चावल के एक दाने से पूरे फसल की गुणवत्ता पहचान लेते हुए, इनकी नीयत को पहचानिए और भाजपा के पक्ष में मतदान कीजिये।

अखिलेश यादव आजकल किसानों की दुहाई दे रहे हैं लेकिन उन्होंने किसानों के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये उनके एकाउंट में भेजे हैं। ■

हमारे कार्य का आधार, जन-जन का विकास : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के औरैया और मैनपुरी में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से परिवारवाद की जगह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद को चुनते हुए डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर अगले पांच साल तक किसी भी किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल भरना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगभग 30,000 करोड़ रुपये की लागत से नंद बाबा डेयरी मिशन के तहत हर किसान को जोड़ने का निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली तथा दीपावली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे। हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे। हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मी बाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे। हम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैब्लेट अथवा स्मार्टफोन वितरित करेंगे। हमारी सरकार बनने पर कानपुर में लेदर पार्क स्थापित किये जायेंगे और 30,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 6 हेल्थ पार्क भी बनाए जायेंगे। हमने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम मिशन जीरो की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, जीका वायरस, जापानी एन्सेफलाइटिस एवं कालाजार जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियों को मिटाने की पहल करेंगे। हम अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे। अगले पांच वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनायेंगे। हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2024 तक हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। हम हर बेघर को घर उपलब्ध करायेंगे। हम प्रदेश में माँ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे।

श्री अमित शाह जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी में डकैती में 72%, लूट में 62%, हत्या में 31%, अपहरण में 29% और बलात्कार में लगभग 50% की कमी आई है। भू–माफियाओं द्वारा कब्जा की गई लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर चला कर अवैध कब्जे से मुक्त कराया है और उस पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। सपा–बसपा की सरकार में जाति विशेष और वर्ग विशेष का काम होता था लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर जन–जन का विकास हो रहा है। सपा–बसपा की सरकार में पुलिस, माफियाओं से डरती थी लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में माफिया, पुलिस को देखते ही भागने लगते हैं। आज आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल में बंद हैं लेकिन सपा की अखिलेश सरकार में ये दनदनाते घूमते फिरते थे। यदि गलती से भी सपा यूपी में सत्ता में आई तो ये माफिया फिर से फेल पर रहेंगे लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में ये जेल में ही रहेंगे। यूपी में हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर माताओं–बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की और अब हम मेरठ, रामपुर,

आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी–टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाया जा सके।

कोविड प्रबंधन की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समय पर साहसिक और कड़े निर्णय न लिए होते तो आज कोविड की स्थिति भारत में कितनी भयावह होती, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेड इन इंडिया वैक्सीन के निर्माण की प्रेरणा दी तो उन्होंने दूसरी ओर मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। यह सिलसिला पिछले दो साल से अनवरत चल रहा है। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कहा था कि यह मोदी वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, इसे मैं नहीं लगाऊंगा। ये बात दीगर है कि उन्होंने खुद डर से चुपके–चुपके वैक्सीन लगवा लिया। आज सोचिये कि यदि वैक्सीन न होता तो क्या हम लोग कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाते!

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 1.67 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलिंडर दिया। अब हमने अपने संकल्प पत्र में निर्णय लिया है कि हम हर साल होली और दिवाली के अवसर पर महिलाओं को एक–एक गैस सिलिंडर मुफ्त देंगे। विगत पांच वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, इसमें से लगभग 2 करोड़ शौचालय अकेले उत्तर प्रदेश में बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 42 लाख आवास यूपी में बना। करोड़ों घरों में बिजली पहुंची, शुद्ध पीने का पानी पहुंचा, गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड बना और किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के एकाउंट में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में 10 विश्वविद्यालय, 77 कॉलेज, 40 मेडिकल कॉलेज, 26 इंजीनियरिंग कॉलेज और हजारों कस्तूरबा विद्यालय खोले गए। लेकिन, अखिलेश यादव ने अपने शासन काल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गरीबों के हित में हो।

अगले पांच वर्षों में हम यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनायेंगे। हम यूपी की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

औरैया में विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि औरैया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की श्रृंखला तैयार करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत कर दी गई है। औरैया से दरियापुर जाने के लिए बस स्टैंड बन रहा है। दरियापुर में फोर लेन बाईपास प्रस्तावित है जो अगले एक साल में बन कर तैयार हो जाएगा। यहाँ अदालत बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, यह भी अगले एक वर्ष में बन कर तैयार हो जाएगा। शेरगढ़ तक फोरलेन मार्ग जल्द ही बन कर तैयार हो जाएगा। पाता में रेलवे ओर्वर ब्रिज बना है, सात नाले और नदियों पर पुल बनाया गया है। इस क्षेत्र में चार ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। इस एक ही जनपद में केवल पांच साल में लगभग 220 पंचायत भवन बनाए गए हैं। भिलाई रिफाइनरी से पनकी कानपुर तक पाइप बिछाने का काम पूरा हो गया है। डिफेंस कॉरिडोर इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा। सपा की अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश में कट्टे और छर्रे बनते थे, आज योगी आदित्यनाथ सरकार में गोले बनते हैं जो देश के दुश्मनों को दहलाते हैं।

मैनपुरी के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मैनपुरी में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है, 40 नए स्वास्थ्य उप–केंद्रों का लोकार्पण किया है और वर्षों से अटके पुल का निर्माण किया है। मैनपुरी में पीएचसी बनाया जा चुका है, अकेले मैनपुरी में 4 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा चुके हैं, लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से मैनपुरी में 27 मार्गों का शिलान्यास हो चुका है और किसान सम्मान निधि के तहत मैनपुरी के किसानों के एकाउंट में लगभग 503 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जा चुके हैं।

श्री शाह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाने का काम किया। सपा और बसपा के समर्थन से केंद्र में 10 वर्षों तक सोनिया–मनमोहन की सरकार चली लेकिन आये दिन आतंकी हमले होते रहते थे और कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। ये श्री नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद पर करार प्रहार किया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी हैं जिन्होंने धारा 370 को खत्म किया, प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई।

जनता से आग्रह करते हुए कहा कि आप यूपी में एक ऐसी सरकार लाइए जो केवल एक परिवार के लिए काम न करे। कुछ दिन पहले एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ छापा पड़ा, उसमें 250 करोड़ रुपये से अधिक का कैश बरामद हुआ लेकिन दर्द अखिलेश यादव जी को होने लगा। कहने लगे कि केंद्र की भाजपा सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। अखिलेश जी, पहले ये तो बताओ कि आपका उस समाजवादी इत्र वाले के साथ रिश्ता क्या है? यूपी की जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहा है। इस बार का यूपी विधान सभा चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ–साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों को भी मजबूत करने का चुनाव है। ■

देश की सुरक्षा खतरे की बात!

पिछले अनेक दशकों से हमारा देश, आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जेहादी संगठनों की कुदृष्टि हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हम लोगों पर रही है। हम–आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को ही निभाना पड़ता है। एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फटते थे, तो किसी दिन दिल्ली में। जयपुर, बेंगलुरू, हैदराबाद, गुवाहाटी, लुधियाना, अगरतला, इंफाल, कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धर्राए, कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए।

जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस दौरान अमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी।

नरेन्द्र मोदी

आपने देखा है, कुछ दिन पहले ही अमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा भी मिली है। कुछ राजनीतिक दल, ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल, वोटबैंक के स्वार्थ में, आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में ही 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर में भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई, तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने का फैसला ले लिया था। ऐसे ही आपको याद होगा, 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को 20 साल की सजा हुई थी। 2007 में लखनऊ, अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे।

2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक काजमी नाम के आतंकी से मुकदमा वापस ले लिया था लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और उस आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसे ही यूपी में एक दो

नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया, और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस इनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं जबकि हमारी सरकार ने **National War Memorial** और **National Police Memorial** बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है, तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं। और मैं आज गुजरात पुलिस की भी प्रशंसा करूंगा कि उसके प्रयासों से आतंकियों के कई मॉड्यूल्स का

आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी।

खात्मा हुआ है।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के दर्जनों देश भारत में बने टीकों के लिए कतार में थे लेकिन इन लोगों ने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कहा गया कि ये भाजपा का टीका है। इस संकट काल में हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा व्यापार करने वालों का भी हाथ थामा है। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग साढ़े 8 लाख रेहड़ी, ठेले वाले साथियों को लोन स्वीकृत किए गए हैं। घोर परिवारवादियों को न तो प्रदूषण से कराहती गंगा मैया की चिंता थी, न गरीब, दलित, पिछड़े परिवार की मां की चिंता थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो आज हर घर जल पहुंचाने में जुटी है। आज़ादी के इतने दशकों तक इन छोटे किसानों की चिंता किसी ने नहीं की। डबल इंजन सरकार ने पहली बार छोटे किसानों को नीति–निर्माण के केंद्र में रखा है। पीएम किसान सम्मान योजना और 60 वर्ष के बाद पेंशन की योजना इसका बड़ा प्रमाण है। पहले कमल पर मतदान, फिर करेंगे कोई दूसरा काम। ■

सपा सरकार ने आतंकियों के मुकद्दमें वापस लिये : योगी

राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती लेकिन सपा, बसपा व कांग्रेस राष्ट्र की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। जनता को सपा से पूछना चाहिए कि वोट बैंक महत्वपूर्ण है या राष्ट्र की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि एक ओर राष्ट्र की सुरक्षा के साथ लोगों के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी सपा है वहीं दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास, सबको सुरक्षा और सबका सम्मान करने वाली बीजेपी है। ये बातें सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली के लालगंज, सरेनी, हरचंदपुर व बछरावां में आयोजित जनसभा में कहीं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। उसमें से कई आतंकी आजमगढ़ के थे जिसमें एक आतंकी के अब्बाजान हैं जो वर्तमान में सपा सरकार के प्रचारक हैं। आज सपा के अध्यक्ष इस मुद्दे पर मौन हैं।

ये अवसर है वोट की चोट से इन लोगों का जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार ने 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। रायबरेली में 81700 से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया। जिले के 3 लाख 60 हजार किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ मिल रहा है। जिले में 50 हजार गरीबों को आवास, 95 हजार वृद्धजनों, 36 हजार निराश्रित महिलाओं को और 12 हजार दिव्यांगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में बीजेपी सरकार बनने पर सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी, अवैध बुचड़खानों को बंद कराने व महिला सुरक्षा का काम किया वहीं साल 2012 में सपा ने सरकार बनने पर आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था।

'पहले विकास का पैसा हड़प लिया जाता था-सीएम योगी'

पहले विकास का पैसा हड़प लिया जाता था। गरीबों का अन्न, एक्सप्रेसवे, सड़कों का पैसा हड़प लेते थे। ये पैसा इत्र वाले मित्र के घर जाता था आज विकास का पैसा विकास पर लगता है। नौजवानों को नौकरी, मेडिकल कॉलेज, सड़क, एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हो रहा है। आज अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में पहले दंगे होते थे सपा के कार्यकाल में 700 से अधिक दंगे, बसपा में 364 दंगे हुए। आज दंगे नहीं होते दंगाईयों को मालूम है कि पीढ़ियां दंगों की प्रतिपूर्ति करते थक जाएंगी। पहले बिजली को भी जाति से जोड़ा जाता था। सपा सरकार में ईद बकरीद पर बिजली आती थी होली दीवाली पर नहीं। आज बिना भेदभाव सबको बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नौजवानों को स्मार्ट बनाने के लिए टैबलेट स्मार्टफोन बांटे पर सपा को बुरा लगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि सरकार बनने पर प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देंगे।

'टीके का भ्रामक प्रचार करने वालों को वोट की चोट दीजिए-सीएम योगी'

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार फ्री में वैक्सीन, टेस्ट, इलाज के साथ राशन की डबल डोज देने का काम भी कुशलतापूर्वक कर रही है। वैक्सीन को मोदी योगी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन बताने वालों को वोट की चोट देकर उनके मुहं पर जोरदार तमाचा मारिए जिससे उनकी जमानत जब्त हो जाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में यूपी के छात्र जो कोटा में फंसे थे उनको बस की सेवा देने से कांग्रेस ने मना कर दिया था इतना ही नहीं कांग्रेस ने 1000 बसों की फर्जी सूची भी दी। ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 हटाने के मामले में बीजेपी का विरोध किया। कश्मीर के मुद्दे पर जहां पाकिस्तान को छोड़ सब देशों ने समर्थन किया पर राहुल ने संसद में इसका विरोध किया।

'बीजेपी की सरकार बनने पर संस्कृत के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति-सीएम योगी'

सीएम योगी ने कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा है कांग्रेस वाले एक्सीडेंटल हिन्दू हैं। मैं कहता गर्व से कहो हिन्दू हैं। सरकार बनने पर पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा इसके साथ ही संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता को तय करना होगा कि बुलेट ट्रेन वाली सरकार चाहिए या पंचर साइकिल। उन्होंने कहा कि न तो हम गौ माता को कटने देंगे न ही अन्नदाताओं की फसल को नुकसान होने देंगे।■

'योगी राज, कानून का राज'

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में हर क्षेत्र में जो काम किया है उसके लिए प्रदेश की 24 करोड़ जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हर वर्ग को अपने साथ रखते हुए जिस तरह योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनकल्याणकारी सरकार चलाई है उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है।

पीयूष गोयल

कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों में योगी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। अगले पांच वर्षों में इसको आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश देश में सुनहरे प्रदेश के रूप में छाप छोड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में वे जब चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो एक दिन में ही लखनऊ समेत कई जिलों में व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्याएं हुई थी। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी, अपराध चरम पर था, आम आदमी डरा हुआ था। वे खुद लखनऊ में व्यापारी श्रवण साहू के घर गए थे। वह मंजर कितना खौफनाक था। आज उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर बढ़ चला है। मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। इससे न केवल यहां बड़े पैमाने पर निवेश आया है बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। गुंडाराज से मुक्त हुआ यूपी भारत के विकास की गाथा लिख रहा है।

किसानों के लिए योगी सरकार ने अभूतपूर्व काम किये हैं जो 2017 से पहले आज तक इस प्रदेश में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच गन्ना किसानों को जितना भुगतान किया गया उसका लगभग दोगुना 1.59 लाख करोड़ का भुगतान 2017 से अब तक किया गया। जिसमें पिछली सरकार का बकाया भी शामिल है। पिछले पांच वर्षों में धान की कुल 275 लाख मिट्रिक टन की क्रय कि गई। जबकि 2012 से 2017 के बीच मात्र 123 लाख मिट्रिक टन खरीद ही थी। इसी तरह योगी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में गेंहू की भी रिकार्ड खरीद की।

प्रधानमंत्री की 2018 में एमएसपी डेढ़ गुणा करने की घोषणा का उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन तो किया ही, साथ ही साथ किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में अनेक प्रयास किये जिसमें कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को सिंचाई व बिजली उपलब्ध कराना प्रमुख रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में लगभग चार करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ा। इसमें एमएसएमई सेक्टर का काफी योगदान रहा। इसका सुपरिणाम यह निकला कि 2017 से पहले बेरोजगारी का जो आंकडा दो अंकों में हुआ करता था वह घटकर चार प्रतिशत रह गया।

प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश का माहौल बनाने में योगी सरकार का जो योगदान रहा उसे पूरा देश याद करेगा। पिछले 5 वर्षों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए नियमों का सरलीकरण और अच्छी कानून व्यवस्था और आधारभूत ढांचा तैयार करने में योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।

पहले प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे जो अब पांच हो गए हैं। पहले एयर कनेक्टिविटी सिर्फ 25 स्थानों तक सीमित थी जबकि आज 75 शहरों से हवाई सुविधा के माध्यम से यूपी जुड़ चुका है। जेवर में बनने वाला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो विश्व में नायाब होगा। कोरोना से जूझते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा तैयार किया। 1947 से अब तक प्रदेश में सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज से जबकि पिछले 5 सालों में इनकी संख्या 30 हो गई। इसी तरह एमबीबीएस की सीट 2017 में उन्नीस सौ हुआ करती थी, जो बढ़कर 3800 हो गयी है।

समाजवादी पार्टी की परिवारवादी सोच सिर्फ एक परिवार का भला सोच सकती है उसके लिए भाजपा की सबका साथ सबका विकास की सोच समझ के बाहर है। यह तो सिर्फ जनता ही समझ सकती है जिसने योगी सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया। गुंडों, माफिया और अपराधियों के दम पर सरकार चलाना एक बात है लेकिन 24 करोड़ जनता के हित के बारे में सोचना, यह सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। ■

कर्तव्य की परिधि "मत-मतदाता-मतदान"

लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जिससे देश प्रदेश समाज व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार मतदाता अपने मतों के प्रयोग से एक सुयोग्य नेता, लोकहितकारी दल, जनकल्याणकारी सरकार को चुनता है। लोकतंत्र में सबका मत समान प्रभाव, अधिकार रखता है। इस लिए सबका कर्तव्य है कि सकल सुमंगलकारी राज व्यवस्था के लिए सोंच समझ कर निश्चित मतदान करें। वैसे परिपक्व लोकतंत्र होने के बाद भी भारत में पूर्व में लोभ, लालच, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, को प्राथमिकता दे कर अनेकों लोग मतदान करते थे। हथियारों के बल पर दबंगई के साथ मतदान में मतो की लूट आम बात होती थी। दारू, रूपया के बल पर वोट खरीदे जाते थे, लेकिन इधर के वर्षों में देश बदल रहा है। चुनाव में तकनीकी प्रयोग, जागरूकता के कारण चुनाव की भी प्रमाणिकता बढ़ी है। देश में मतदान वही करता है जो सोचता है नही तो केवल सुधार, परिवर्तन, विकास की बात करता है मतदान के लिए जाता नही है। लेकिन जो करता है वह प्रत्याशी, दल, नेता नीति सबके बारे में विचार करता है। तब वह ईमानदार, सक्षम, स्थायी समाधान देने वाली सरकार के पक्ष में मतदान करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रदेश देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है इसलिए सोंच समझ कर निर्भीक हो मतदान करने के पहले विचार करें फिर मतदान करें।

साधक राजकुमार

सांस्कृतिक, वैचारिक आस्था की पहल –

पांच शताब्दियों के सतत संघर्ष के उपरान्त 05 अगस्त 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा श्रीराम के मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण का शुभारम्भ। 221 मीटर ऊँची श्रीरामजी की प्रतिमा। रामायण संग्रहालय। 225 करोड़ बजट। 25 एकड़ में निर्माण चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम जिससे दुनिया भर में बिखरे भारतवंशी अयोध्या से जुड़े जिसमें 9 लाख दीपकों से विश्व रिकॉर्ड बना। श्रीराममन्दिर पर डाक टिकट। अयोध्या से जनकपुर बस सेवा। रामायण एक्सप्रेस द्वारा 16 दिन में भगवान श्रीराम जी से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन। तीर्थस्थलों के लिए अन्य विशेष ट्रेनों का संचालन। फैजाबाद जिला कमिश्नरी, नगर निगम तथा रेलवे स्टेशन नाम परिवर्तित। क्रूज सेवा प्रस्तावित। इन्टरनेशनल एयरपोर्अ। बुलट ट्रेन।

प्रयागराज कुम्भ पिछला रिकार्ड 9 करोड़, इस बार 24 करोड़ लोग आये। 1300 से बढ़ा कर 4200 करोड़ बजट किया। 191 देशों से लोग आये। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रत्येक हिन्दू के लिए आत्मसम्मान का विषय तो है ही, साथ पर्यटन अर्थव्यवस्था के साथ–साथ स्थानीय शिल्पों के पुनरोदय का माध्यम भी है। अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा 100 वर्ष बाद अमेरिका से वापस लाए। काशी में क्रूज सेवा शुरू। बरसाना में भव्य रंगोत्सव। मथुरा में कृष्णोत्सव। जेल व थानों में फिर से कृष्ण जन्मोत्सव प्रारम्भ। केदारनाथ धाम सहित चारों धामों का विकास। कावंड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा व डी0जे0 से प्रतिबन्ध हटाया। वैष्णों देवी जाने हेतु कटरा तक सीधी रेल सेवा। गुरुदासपुर जिले में डेराबाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण । सउदी अरब (अबूधाबी) में पहला मन्दिर निर्माण। ढाकेश्वरी देवी, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर (जनकपुर) में पूजा प्रधानमंत्री जी द्वारा। 500 कुन्तल चन्दन लकड़ी पशुपतिनाथ मंदिर को भेंट। ब्रज, विन्ध्य, चित्रकूट, नैमिषारण्य विकास परिषद गठित।

धार्मिक पर्यटन- सांस्कृतिक एकात्मता, उत्थान, विकास के लिए प्रयास –

रामायण सर्किट – अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट। बौद्ध सर्किट – कपिलवस्तु, कौशाम्बी, कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ, श्रावस्ती। बुन्देलखण्ड सर्किट – बिठूर, चित्रकूट, झाँसी, कालिंजर, महोबा। कृष्ण बृज सर्किट – आगरा, मथुरा, वृन्दावन। अवध सर्किट – लखनऊ, नैमिषारण्य, अयोध्या। विंध्य सर्किट – वाराणसी, चुनार, विंध्याचल। शक्तिपीठ सर्किट – विंध्याचल, बलरामपुर, वाराणसी, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र और सहारनपुर। आध्यात्मिक सर्किट – (स्पिरीचुअल सर्किट)– बिजनौर, मेरठ, कानपुर, कानपुर देहात, बाँदा, गाजीपुर, सलमेपुर, घोसी, बलिया, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, फतेहपुर, देवरिया, महोबा, सोनभद्र, चन्दौली, मिश्रिख एवं भदोही के कुल 46 पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। आगरा, अलीगढ़, कासगंज, उन्नाव, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मीरजापुर, गोरखपुर, डुमरियागजं, बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़, कैराना, बागपत एवं शाहजहाँपुर के कुल 39 पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है, जहां तेजी से कार्य चल रहा है। गोरखपुर, देवीपाटन और डुमरियागंज के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। जेवर, दादरी, सिकन्दराबाद, नोएडा, खुर्जा, बाँदा के पर्यटन विकास कार्य कराये जा रहे है। जैन सर्किट – मेरठ, आगरा, कौशांबी, वाराणसी, देवरिया, अयोध्या, श्रावस्ती और फर्रुखाबाद। महाभारत सर्किट – हस्तिनापुर (मेरठ), काम्पिल्य (फर्रुखाबाद) और अहिच्छत्र (बरेली), बरेली में आवंला तहसील में उत्तरी पान्चाल।

''नेता, नीति, नियति पर विश्वास''

योगी है तो यकीन है---ईमानदारी का

योगी हैं तो यकीन है--भय मुक्त प्रदेश का

योगी हैं तो यकीन है-सुंदर दमदार प्रशासन का

योगी है तो यकीन है-बिजली के बराबर रहने का

योगी हैं तो यकीन है--चौड़ी चौड़ी मखमली सड़कों के जाल का

योगी हैं तो यकीन है---कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता

योगी हैं तो यकीन है--हर गरीब को अपना घर मिलने का

योगी हैं तो यकीन है--हर गरीब के मुफ्त इलाज का

योगी हैं तो यकीन है--किसान सम्मान निधि पाने का

योगी हैं तो यकीन है--नकल मुक्त परीक्षाएं सम्पन्न कराने का

योगी हैं तो यकीन है--योग्यता के आधार पर

सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों के पाने का

योगी हैं तो यकीन है--उ प्र को मेडिकल हब बनाने का

योगी हैं तो यकीन है---एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने का

योगी है तो यकीन है--हवाई अड्डों का जाल बिछाने का

योगी है तो यकीन है--चहुतरफा विकास करके नंबर 1 प्रदेश बनाने का।

बैद्ध सर्किट एवं उसका महत्व –

ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का काफी समय इस परिपथ में व्यतीत किया था। सर्किट में बुद्ध के स्तूप, मठ...आदि शामिल होंगे। धार्मिक पर्यटक और श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के इस सर्किट में भगवान बुद्ध के जीवन, उनके द्वारा दी गयी शिक्षाओं और व्यवस्थाओं को जान सकेंगे और ज्ञानार्जन कर सकेंगे। बुद्ध सर्किट और कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्मित होने से दुनिया भर के बौद्ध, विशेषकर श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, जापान, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस....आदि, भारत के साथ तेजी से कनेक्ट होंगे। इसमें प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की एक्ट ईस्ट की नीति प्रेरक साबित होगी जो भारत के साथ पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के सामरिक एवं कूटनीतिक संबंधों को तो मजबूत करेंगे ही साथ पर्यटन को बढ़ावा भी देंगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए श्रेष्ठ पर्यटन डेस्टिनेशन बनेगा। इससे विदेशी मुद्रा का बड़ी मात्रा में आगमन होगा जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान तो देगा ही स्थानीय लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा।

वैचारिक कार्य नीति-सिद्धान्त वैभव ाली भारत बनाने के प्रयास –

इलाहाबाद का प्रयागराज एवं मुगलसराय रेलवेस्टेशन का नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय व फरह स्टेशन का नाम पं0 दीनदयाल धाम परिवर्तित किया। प्रदेश के लगभग हर विश्वविद्यालय पं0 दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च चेयर की स्थापना। हज यात्रा के लिये अनुदान बन्द। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा रोजा इफ्तार बन्द। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया। सिंधुदर्शन यात्रा पर भी 20 हजार अनुदान शुरू। अवैध बूचड़ खाने बन्द। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून । 90 देशों में योग पाठ्यक्रम आरंभ। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ताज नहीं काशी मन्दिर दर्शन व आरती दिखाना तथा ताजमहल नहीं गीता भेंट करना। सरदार पटेल की प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) का निर्माण। छब्म्त्ज के पाठ्यक्रम में कांग्रेस सरकार द्वारा हटाये गये हिन्दू संस्कृति के मुख्य वाहको को शामिल किया इनमे स्वामी विवेकानंद, श्री अरविन्द, महाराणा प्रताप, बाजीराव बल्लाल, सूरजमल, छत्रपति शिवाजी आदि शामिल है। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल कर डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया। जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण रोका। धर्मान्तरण विरोधी कानून बनाया। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नामकरण छत्रपतिशिवाजी के नाम पर किया गया।

राष्ट्रीयता के कार्य जिसे भारत की एकता अखण्डता स्वाभिमान बढ़ा–

धारा 370 हटाकर एक देश एक निशान एक विधान का कार्य पूर्ण किया। बौद्ध बाहुल्य लद्दाख को स्वतन्त्र केन्द्र शासित राज्य बनाकर वहाँ की संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग हेतु चीन से समझौता। सरदार पटेल की प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) का निर्माण। म्यांमार व पाक में 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अमेरिका, इजराइल के बाद भारत तीसरा देश। विंग कमांडर अभिनन्दन की 57 घंटे में पाक से भारत वापसी। घाटी के 500 नेताओं की सुरक्षा व सुविधा बन्द–250 गाड़ी व 2000 जवान खाली हुए। विदेशी फंडिंग रोकने हेतु 13,000 से अधिक एन0जी0ओ0 का पंजीकरण निरस्त–जिससे 40: विदेशी फंडिंग रूकी। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। मानवता के अमूल्य धरोहर महाकुम्भ के दौरान प्रयागराज में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने 1 माह में स्नान

किया तथा इस दिव्य–भव्य–कुम्भ की व्यवस्था एवं स्वच्छता की चर्चा वैश्विक स्तर पर हुयी।

सुशासन : सुराज स्थापना के सार्थक प्रयास –
2017 से पहले प्रदेश में अराजकता एवं गुण्डागर्दी का माहौल था जिसे समाप्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने माफिया गिरोहों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की एवं उनकी अकूत अवैध सम्पत्ति कुर्क करायी साथ ही अवैध वसूली के तहत जमा की गयी हजारों कराड़े धनराशि की सम्पत्ति का ध्वस्तिकरण एवं अवैध खातों को सीज किया गया। परिणामस्वरूप नागरिकों में व्याप्त भय समाप्त हो उनमें विश्वास का निर्माण हुआ। माफियाओं की 1866 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त या ध्वस्त। 150 इनकाउंटर, 3427 अपराधी घायल, 44,759 पर गैंगेस्टर, 630 पर रासुका। 11,864 इनामी अपराधी गिरफ्तार। ब।। द्वारा पाक बांग्ला देश के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना। ब।। के विरोध में तोड़–फोड़ कर क्षति पहुंचाने वालों से वसूली। सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था आधारित नई भर्ती प्रक्रिया अपनाने से अधिसंख्य गरीब परिवारों के बच्चों को भी नौकरी बिना भेदभाव के मिली। प्रदेश में एकांगी विकास परम्परा के स्थान पर सर्वांगीण एवं सर्वसमावेशी विकास की परम्परा आरम्भ हुयी। प्रदेश की विकास योजनाओं में पहली बार गाँव को विकास की धारा में प्राथमिकता से शामिल किया गया जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की धारा में सहभागी हो रहे हैं। पुलिस एवं प्रशासन के लचर तथा भ्रश्ट अधिकारियों पर व्यापक कार्यवाही पहली बार हुयी। सम्पूर्ण प्रदेश के ग्राम सचिवालय खोलने की योजना मूर्त रूप लेने लगी जिससे जनता को छोटे–छोटे सरकारी कामों के लिए ब्लाक एवं तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें।

सुरक्षा : आन्तरिक वाह्य सुरक्षा की सुदृढ़ योजना – 2017 से आज तक कोई भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों से पूरी वसूली की गयी। प्रदेश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से 214 नये थाने खुले। लखनऊ, नाऐडा, वाराणसी, कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट बनाया। लखनऊ में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रारम्भ। 1.43 लाख पुलिस भर्ती।

महिला : समाज सशक्तिकरण के अभिनव प्रयोग – तीन तलाक विदेशी कुप्रथा पर सरकार द्वारा रोक। 1.52 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह। स्नातक तक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। 1.67 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। लडकियों के विवाह में सरकारी सहयोग। कोरोना काल में निराश्रित हुयी महिलाओं को रू0. 4000/– मासिक सहयोग एवं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा आंगनबाड़ी में विशेष भर्ती अभियान।

युवा एवं खेल – एक करोड़ युवाओं को फ्री स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण की शुरूआत। टोक्यों ओलम्पिक पदक विजेताओं को 42 करोड़ दिए। कुश्ती व बैडमिंटन खेल गोद लिया। मेरठ में मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय।

उद्योग – प्रदेश में अराजकता एवं माफियागीरी एवं सरकारी पेचदगियों के कारण पिछड़े हुये
औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया जिससे बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन भी हुआ। वन डिस्ट्रिक वन प्रॉडेक्ट योजना का व्यापक प्रभाव हुआ है और प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रसिद्ध कला, खानपान एवं घरेलू उद्योग को वैश्विक बाजार मिला।

रोजगार – 4.50 लाख को सरकारी नौकरी। 3.50 लाख को संविदा पर नौकरी। वन डिस्टिक . वन प्रोडक्ट द्वारा 25 लाख लोगों को रोजगार। 1.50 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों की भर्ती की गयी। नये तीर्थाटन एवं पर्यटन योजना से भी रोजगार सृजन होंगे तथा युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी।

किसान – 20 चीनी मीलों का आधुनिकीकरण एवं बन्द पड़ी चीनी मिलें फिर से शुरू की गयी। 1.50 लाख करोड़ रूपये गन्ना का भुगतान किया गया। धान एवं गेहूँ की सरकारी खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि हुयी और यह आकंड़ा कई गुना बढ़ गया। 2 हजार नये नलकूप व 787 खराब नलकूपों की मरम्मत। 1.5 लाख किमी नहर की सफाई व पानी दिया। 2,53,9800 किसानों को 6,000 रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 37,521 करोड़ दिए। गौशालाओं में 5.87 लाख गोवंश संरक्षित व गोवंश रखने पर प्रति गोवंश 900 रू0 अनुदान प्रतिमाह।

बिजली, आवास, शौचालय – 1.41 लाख विद्युत कनेक्शन देकर उ0प्र0 देश में प्रथम स्थान पर। पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति बिना भेदभाव के हो रही है। विद्युत उत्पादन 28,422 मेगावाट जो पूर्व से 6,000 मेगावाट अधिक है। 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता की अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन। 2

करोड़ 60 लाख 81 हजार एल0ई0डी0 का वितरण। खराब ट्रांसफर बदलने का समय शहर में 24 घंटे व ग्रामीण में 48 घंट किया। 42 लाख आवास निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा। मुख्यमंत्री आवास योजना द्वारा (ग्रामीण में) 1,08,495 लाख आवास निर्माण। 2.61 करोड़ शौचालय व 58758 सामुदायिक शौचालय तथा 4500 पिंक टॉयलेट का निर्माण।

सड़क – 341 किमी पर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण। 297 किमी बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे का निर्माण। 594 किमी0 गंगा एक्सप्रेस–वे का भूमि पूजन। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे निर्माणाधीन। बलिया लिंक एक्सप्रेस–वे प्रस्तावित।

मेट्रो – 10 शहरों में मेट्रोरेल परियोजना।

एयरपोर्ट – 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण। 8 नये एयरपोर्ट संचालित। 13 अन्य एयरपोर्ट व 7 हवाई पटट्ी का विकास।

शिक्षा – 1.38 लाख सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया। 771 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की स्थापना। 9 राज्य विश्वविद्यालय व 51 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये। प्रदेश के सभी मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले गये है।

स्वास्थ्य – 9 नये मेडिकल कॉलेज चालू। वर्तमान में 59 जिलों में न्यूनतम 1 मेडिकल कालेज क्रियाशील। 16 जिलों में पीपीपी माडल पर नये मेडिकल कालेज खाले ने की प्रक्रिया प्रारम्भ। डठठै की 938 सीटें बढ़ी तथा 900 सीटें और बढ़ने वाली है। डव – डै की 127 सीटे बढ़ी। 11,004 भारतीय जन औषधि केन्द्र खुले जहां सस्ती दवा मिलती है। 9,512 चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया। 555 आक्सीजन प्लांट स्वीकृत, जिनमें से 392 चालू हो गये। गोरखपुर व रायबरेली एम्स क्रियाशील हैं। गोरखपुर व भदोही में वेटनरी विश्वविद्यालय का निर्माण। अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय–लखनऊ का निर्माण प्रारम्भ। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारम्भ।

कोरोना माडल – उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल कोविड प्रबन्धन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसके सम्बन्ध में दुनिया के अलग–अलग समाचार पत्रों में आर्टिकल भी छपे तथा W.H.O. ने इसकी प्रशंसा की। कोरोना काल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रवासी प्रदेश वासियों, श्रमिकों के आवागमन का कुशल प्रबन्धन कर शासन ने जनता का दिल जीता। इस काल में निःशुल्क राशन व दवाईयों का वितरण किया। मुफ्त कोरोना जांच व मुफ्त टीका। सरकारी दिशा निर्देशों के कारण पुलिस का भी मानवीय चेहरा जनता के सामने आया। पुलिस के डायल 112 के वाहनों ने सुरक्षा के साथ ही दवा एवं जरूरी सामानों को भी लोगों के घर तक पहुँचाने का काम भी बखूबी किया।

महापुरूषों का सम्मान – महाराजा सुहेलदेव स्मारक हेतु 25 करोड़ दिये। बहराइच मेडिकल कॉलेज व आजमगढ़ विश्वविद्यालय को महाराजा सुहेलदेव के नाम किया। डॉ0 अम्बेडकर की 125 जयन्ती पर पंचतीर्थ (महू, दीक्षा भूमि, इंदुमिल, हलीपुर और चैतन्य भूमि) का विकास।

वैश्विक स्तर पर भारत – आज भारत की सामरिक, राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति को विश्व आदरपूर्वक स्वीकार कर रहा है तथा विश्व के अधिसंख्य देश भारत को एक सशक्त देश के रूप में तथा देश प्रधानमन्त्री को सशक्त एवं सर्वस्वीकार्य वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी को दुनिया के कई देशों अपने सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया है जो देश के लिए गर्व का विषय है।

अन्य उल्लेखनीय कार्य – 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन–प्रति कार्ड 35 किलों/प्रति व्यक्ति 5 किलो। 42 करोड़ पौधारोपड़। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण नाऐडा में प्रारम्भ। चर्चा करने के बिन्दु – राममन्दिर का विरोध करने वाले केजरीवाल आज दिल्ली की जनता को अयोध्या दर्शन के लिए भजे रहे हैं एवं खुद भी अयोध्या जाकर दर्शन, पूजन कर हिन्दुत्वादी दिखाने की कोशिष कर रहे हैं। राहुल– अयोध्या दर्शन, तिलक, जनेऊ धारण, हम हिन्दू है बोल रहे। प्रियंका–मंदिर–मंदिर दर्शन, तिलक, गंगा स्नान कर रही हैं। यह हमारी हिन्दुत्वादी एवं राष्ट्रवादी सरकार की स्पष्ट नीति के कारण ही दिख रहा है। सपा आतकंवादियों के मुकदमें वापस लिये। कब्रिस्तान की वाउंड्री हेतु धन देना। केवल मुस्लिमों को छात्रवृत्ति देना।

मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने आत्म निर्भर, स्वाभिमानी, विकसित भारत बनाने के दिशा में अनेक प्रयास किये जिसको मोदी जी कहते हैं इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए **"सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास"** सामुहिक होना चाहिए जिसकी पहली शर्त मतदान कर हम अपना विश्वास व्यक्त करें। आइये राष्ट्रहित में सरकार चुने। ■

लोकतन्त्र के महापर्व हमारी भूमिका

उत्तर प्रदेश विधानसभा– 2022 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इस समय हमारे पास सुअवसर है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। हमें अपने मत को सार्थक बनाने का। हमें अपने प्रिय प्रदेश की बागडोर 5 वर्षों के लिए किसके हाथ में सौंपनी है, इसका विचार करने का अवसर है यह। समय है अपने मत के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भविष्य–निर्धारण का।

हमें भय, भूख, भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार बनानी है। एक ऐसी सरकार जो सांस्कृतिक, संस्कारित, राष्ट्रवादी एवं रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था दे सके। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा–व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। ऐसी सरकार जो बिजली, पानी, सड़क की अच्छी व्यवस्था देने वाली हो। जिस पर माताओं–बहनों को विश्वास हो सके, जो किसानों की चिन्ता कर सके। हमें ऐसी सरकार चुननी है जो हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत का सम्मान करने व उसे आगे बढ़ाने वाली हो।

आइए! ऐसी सरकार का चयन करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बल देने वाली हो, प्रदेश को प्रगति पथ पर बढ़ाने वाली हो, बिना भेद–भाव के विकास करने वाली हो एवं जिसका नेतृत्वकर्ता सक्षम, कर्मठ व ईमानदार हो।

मेरा मतदान – देश का सम्मान **मेरा मतदान – उ. प्र. का उत्थान**

मत देते समय विचार करें कि आपका मत किसे जा रहा है.......

❖ उसे जो शुरू से श्रीराम मन्दिर बनाने के पक्ष में खड़ा रहा और उसके लिए संघर्ष किया	या	उन्हें जो राम मन्दिर का विरोध करते हुए वहाँ मस्जिद या अस्पताल बनाने की बात करते रहे ?
❖ जो सम्पूर्ण प्रदेश को 24 घन्टे बिजली देने वाला है	या	उनको, जो अपने गृह जिलों की विशेष चिन्ता करते हैं ?
❖ जो माताओं, बहनों, बहुओं को सुरक्षित आने–जाने का माहौल देता है	या	उसे जिनकी सरकार में महिलाएँ दिन में भी अकेले निकलने में असुरक्षित महसूस करती हों ?
❖ जो अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं उसे	या	उन्हें जो वसूली, छिनैती, हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देते हों?
❖ जो धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने वाले हैं उनको	या	धर्मांतरण को बढ़ावा देने वालों के संरक्षकों को ?
❖ शिक्षा के विकास हेतु 9 नये विश्वविद्यालय खोलने वालों की सरकार चाहते हैं	या	नकल वाली परीक्षा कराकर युवाओं का भविष्य चौपट करने वालों की ?
❖ प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने वालों की सरकार बनाना चाहते हैं	या	सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्रों को ही प्रदेश मानकर काम करने वालों की ?

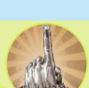

❖ विचार करिए, आप उन्हें वोट देना चाहते हैं जो किसानों के सच्चे हितैषी हैं और उनके कल्याण के कार्य करते हैं	या	उन्हें, जो किसानों के धन को अपने लिए लूटते हैं?
❖ प्रदेश में रामायण, महाभारत, बुन्देलखण्ड, कृष्ण–ब्रज, अवध, विन्ध्य, शक्तिपीठ, जैन और बौद्ध सर्किट के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित कर उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले की सरकार चाहते हैं	या	❖ प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षा कर सिर्फ ताजमहल की ही ब्रांडिंग करने वालों की ?
❖ आप अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मन्दिर एवं काशी में श्रीविश्वनाथ धाम परिसर का निर्माण व विस्तार करने वालों की सरकार चाहते हैं	या	मात्र कब्रिस्तानों की चारदीवारी कराने वालों की?
❖ विचार करिए– आप राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वालों की सरकार बनाना चाहते हैं	या	गुलामी की संस्कृति का पालन–पोषण करने वालों की ?
❖ जम्मू–कश्मीर की विघटनकारी धारा–370 एवं 35–A को हटाकर अखण्ड भारत बनाने वालों की सरकार चाहते हैं	या	धारा–370, 35–A और अलगाववादियों के समर्थन में खड़े होने वालों की ?
❖ सरकारी नौकरियों में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कर समान अवसर देने वाली सरकार बनानी है	या	इनको बढ़ावा देने वाली ?
❖ प्रदेश के उद्योग धन्धों को चौपट कर प्रदेश के नागरिकों का पलायन कराने वाली सरकार चाहिए	या	हर जिले के लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए 'वन डिस्टिक : वन प्रोडक्ट' जैसी रोजगारपरक योजना से लाखों युवाओं को नये रोजगार देने वाली?
❖ मतदान से पहले यह विचार करना भी जरूरी है कि आप वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाने वालों की सरकार चाहते हैं	या	भारत को कमजोर करने वालों की ?

आइए ! अपनी मतदान तिथि पर 'पहले मतदान : फिर जलपान' के संकल्प संग अपना मतदान करें एवं सभी का मतदान करायें। – लोक जागरण मंच

सुशासन में नागरिक सुरक्षा

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। चुनाव चाहे केन्द्रीय स्तर के हों या प्रादेशिक स्तर के विधि का शासन एवं लोक व्यवस्था सदैव आमजन हेतु केन्द्रीय मुद्दा होता है। विधि का शासन एवं लोक व्यवस्था भारतीय संविधान का आधारभूत एवं मौलिक तत्व है तथा यह जनता हेतु किसी सरकार एवं सत्ताधारी दल की सक्षमता का परीक्षण करने के लिए सर्वाधिक सरल एवं मूर्त मानदण्ड होता है। वर्तमान विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश की जनता हेतु भाजपा साशित समय अन्तराल में शांति एवं समरसता की माननीय योगी जी की सरकार में उकेरी नवीन इबारत का परीक्षण करने एवं व्यवस्था को पुनः स्थापित करने एवं आगे भी अनवरत जारी रखने का चुनाव है। किसी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए शांति एवं समरसता वो आवश्यक तत्व हैं जो समाज की प्रगति हेतु उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। शान्ति एवं समरसता स्थापित करने हेतु विधि का शासन एवं लोकव्यवस्था आवश्यक तत्व हैं। विधि स्थापना हेतु तथा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हितों को सुनिश्चित करने हेतु शासक एवं शासन व्यवस्था को **परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां** के सिद्धान्त का अनुगमन करना होता है। जब लोक व्यवस्था विधि के अनुरूप एवं विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया के अनुसार सुस्थापित होती है तो समाज समरस एवं सर्वांगीण रूप से सार्वजनीन विकास की ओर अग्रसर होता है एवं नागरिकों के मन मस्तिष्क में सन्मति, सहमति एवं सद्भावना का उदय होता है एवं समाज की लौकिक उन्नति भी दिन दूनी रात चौगुनी होती है। रामचरित मानस में कहा भी गया है **'जहाँ सुमति तहां सम्पत्ति नाना'** उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार रामराज्य की संकल्पना को ही तो चरित्रार्थ करने का प्रयास कर रही है। सरकार के पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान दिया है।

सौरभ चन्द्र पाण्डेय

भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के लोक कल्याण पत्र में राज्य में रामराज्य की अवधारणा को स्थापित करने का संकल्प किया था साथ ही प्रदेश से गुंडाराज को जड़ से खत्म करने का वादा किया था। सरकार स्थापित होते ही मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर। योगी सरकार के शासन काल में, कभी पुलिस प्रशासन को आंख दिखाने वाले माफियाओं, अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। पुलिस ने न सिर्फ अनेकों आततायियों को उनका प्राप्तव्य उपलब्ध करवाया अपितु प्रदेश भर में असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कार्रवाई कर उनके मनोबल को ध्वस्त किया है साथ ही साथ प्रदेश के दो दर्जन से अधिक बड़े माफियाओं को जेल में धकेल कर उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधि व्यवस्था की स्थापना हेतु इष्टतम रूप से कार्य किया है। यही कारण है कि आज कानून व्यवस्था के मामले में बड़े–बड़े विशेषज्ञ भी देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के लॉ–एंड– ऑर्डर के प्रतिमान को अहम बता रहे हैं।

एक काल खण्ड था जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों के चंगुल में थी। 2017 से पूर्व के कालखंड पर जब गौर किया जाता है तो यह विदित होता है कि प्रदेश हर छठवें दिन दंगों की आग में झुलस रहा होता था। अखबारों के पन्ने हत्या, डकैती, महिला अपराध की खबरों से भरे रहते थे। सत्ता का संरक्षण पाकर पेशेवर अपराधी प्रदेश में खुलेआम घूमते थे और दहशत फैलाना इन अपराधियों की लगभग प्रवृत्ति सी बन गया था तथा उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में अपराध प्रदेश के रूप में होती थी। उत्तर प्रदेश की छवि को योगी सकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बदलने का काम किया है। योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले प्रदेश की क़ानून व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों एवं अटल इरादों का नतीजा है कि प्रदेश भयमुक्त, अपराध मुक्त और दंगामुक्त हुआ और अपराधियों के मन में प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को लेकर भय का माहौल बना। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों, माफियाओं और दंगे की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों पर कहर बरपाया। आज स्थिति है अपराधी या तो जेल की सीमा के अन्दर हैं या प्रदेश की सीमाओं के बाहर हैं।

माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है उसी का नतीजा है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है। 2017 से पहले प्रदेश में खूंखार अपराधियों का बोलबाला था जिन्हें नियंत्रित करना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। योगी सरकार ने आते ही इन खूंखार अपराधियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया है। जहां पुलिस के एनकाउंटर में यूपी के 150 से ज्यादा बदमाश मार गिराए गए वहीं करीब 3 हजार से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए, प्रदेश में ऐसा पहली बार था जब अपराधी खुलेआम नहीं बल्कि जेल में रहना पसंद कर रहे थे। योगी सरकार ने प्रदेश में करीब 43294 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेलों में बंद किया साथ ही साथ 630 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया। आज प्रदेश में पुलिस का खौफ़ इस कदर हावी है कि अपराधी जमानत कराने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बल्कि जमानत ख़ारिज करवाकर कर जेल में ही रहना चाहते हैं।

कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार के उठाए गए कदमों से उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है, 2017 से पहले और उसके बाद 2020 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि डकैती में 55%, लूट में 30%, हत्या में 21% और फिरौती सम्बन्धी मामलों में 46% की कमी आई है। योगी सरकार के आते ही प्रदेश में अपराधियों से पीड़ित व्यक्ति का तत्काल मुकदमा दर्ज करने और ऑनलाइन एफ0आई0आर0 करने के आदेश दिए गए थे, उन्हीं का परिणाम है कि अब कोई भी पीड़ित व्यक्ति बिना डरे, बिना किसी के प्रभाव में आए अपनी समस्याएं और अपने साथ हुए अपराध को पंजीकृत करा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा प्रश्न था, जिसका उत्तर योगी सरकार ने निकाला और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए तमाम प्रयास किए। योगी जी ने सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन कर स्कूल–कॉलेजों के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले गुंडों और मनचलों पर लगाम कसी। वहीं केंद्र सरकार से मिलने वाले निर्भया फंड का उपयोग करके योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वूमेन पावर लाइन, 1090, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत और सक्रिय किया। इतना ही नहीं सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक पैट्रोलिंग शुरू की जिसमें महिला कांस्टेबल्स की तैनाती की। महिलाओं की सहायता के लिए सरकार ने प्रदेश भर में पिंक बूथ बनाए जहां केवल महिला पुलिस कर्मी तैनात की गईं। महिला पुलिस कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर महिला पुलिस

कर्मियों की भर्ती का अभियान चलाया।

पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए बड़े स्तर पर अभियान संचालित किए, इसका नतीजा है कि एन0सी0आर0बी0 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2016 में जहां रेप के 4,816 मामले सामने आए तो वहीं 2020 में संख्या घटकर 2769 तक आ गई। यही नहीं बलात्कार के प्रयास के 2016 में जहां 1958 मामले थे, साल 2020 में घटकर 251 पर आ गए हैं। यौन अपराध के मामलों में 2017 से पहले यूपी शीर्ष पांच राज्यों में था, अब वह 17वें स्थान पर है। ये योगी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि जो महिलाएं अपने ऊपर हुए अपराध और अनाचार को अपराधियों और समाज के भय से दर्ज़ कराने में डरती थी उन्हें साहस मिला और पुलिस प्रशासन से उन्हें सहायता मिली। महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील होकर प्रशासन ने काम करना शुरू किया और पुलिस और एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोका जा सके और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

आज जब लोकतंत्र के पर्व में हर नागरिक मतदान के जरिए सुशासन स्थापना के यज्ञ में अपने हिस्से की आहूति दे रहा है तब ये जरूरी हो जाता है कि वो विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के सुशासन के दावों को वर्तमान की सरकार के कार्यों के साथ कसौटी पर कसे और उसके कामकाज को आधार बनाकर अपना फैसला करें। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जो **'लोक कल्याण संकल्प पत्र'** जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि –

- सरकार बनने पर गुंडे, अपराधी और माफ़िया के खिलाफ कार्यवाही दृढ़ता से आगे भी जारी रखी जाएगी।
- प्रदेश के सभी 18 मण्डलों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट स्थापित होगा।
- तहसील स्तर पर तहसील दिवस के दौरान जनता दरबार का आयोजन जारी रखेंगे।
- प्रदेश की पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
- लव ज़िहाद के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की सजा और ₹1 लाख के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित होगा।
- आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद में एंटी–टेररिस्ट कमांडो सेंटर का निर्माण पूर्ण करेंगे साथ ही मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर एवं बहराइच में इसी तरह एंटी–टेररिस्ट कमांडो सेंटरों का निर्माण होगा।
- प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क (सी.एच.डी.) स्थापित किया जाएगा
- सभी पुलिस कर्मियों (महिलाओं एवं पुरुषों) के लिए बैरक की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।
- पुलिस विभाग के कर्मियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों का निर्माण, मरम्मत आदि का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे।

प्रदेश की जनता ने सुशासन के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी को शासन का उत्तरदायित्व दिया था। अब जब फिर 2022 में पुनः सरकार के निर्वाचन हेतु जनसहभागिता का अवसर है तब प्रदेश की जनता निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के **"सोच ईमानदार, काम असरदार"** के ध्येय वाक्य को शिरोधार्य करेगी। ■

''सर्व पंथ समादार भाव''

वर्तमान में देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही हैं वो भारतीय संस्कृति, दर्शन के आधार पर ''**सर्वे भवन्तु सुखिनः**'' की संकल्पना को साकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जिनका मूल मंत्र है ''**अन्त्योदय**'' इनका संकल्प है।

पूजा पद्धति के आधार पर भारत में सभी मत मतान्तर पंथ को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, शैव, वैशणव सभी मिल जुल कर प्रेम, स्नेह के साथ रह, भारतीय होने पर गर्व करें। इसका निरन्तर प्रयास करती है।

धम्म संदेश

भदंत शांति मित्र

आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाज में जाति, पंथ वर्ग आदि की भिन्नताओं एवं विषमताओं को लेकर त्राहि–त्राहि हुई है। वर्तमान में ही हमारी केन्द्रीय सरकार के अगुवा युगपुरूष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अगुवा परम पुज्यनीय मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं अन्य कई प्रदेश सरकारें धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष समाज तीव्र गति से वैश्विक एकता एवं शांति हेतु आगे बढ़ रही है। आज मतदान की निर्णायक बेला है। हम सभी जाति, पथ के लोग आपस में भाई–चारा बढ़ा कर प्रदेश और भारत राष्ट्र को शक्तिशाली बनाकर आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, माफिया, गुण्डाराज, भ्रष्टाचार से मानवता और मानवीय मूल्यों की रक्षा करें।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के सराहनीय प्रयासों से गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबको समाज की मुख्य धरा में लाने के लिए हर घर को बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क के साथ ही घर गरीब को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन कृषकों को रू0 6000/– वार्षिक, शौचालय, आवास, वैवाहिक अनुदान, चिकित्सीय सुविधायें, निःशुल्क कोचिंग सुविधा एवं वैक्सीन की निःशुल्क सुविधायें प्रदान की जा रही है।

हमसें लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा भोगी को संज्ञान में लेते हुए समाज को टूटने और भ्रमित होने से बचाकर राष्ट्रधम्र को अपनाकर आदिकाल से चली आ रही सनातन भारतीय संस्कृति एवं ध्यान योग द्वारा गांव, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। रूढ़ीवादी, अंधविश्वासी, कट्टरपंथियों से रक्षा करनी है।

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के मूल में सामाजिक समानता निहित है। सम्मान की समानता, कानून में समानता, अधिकारों में समानता अवसर की समानता, मानवीय गरिमा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया और जीवन पर्यन्त संघर्षरत रहे।

इस तथ्य को मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र सरकार ने आदर और सम्मान दिया है और पहचाना है। इस क्रम में सरकार ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों को

स्मारक के रूप में विकसित किया एवं पंचतीर्थ योजना के नाम से लागू किया है। इन पंचतीर्थों को 1. जन्म भूमि महू, म0प्र0, 2. अम्बेडकर स्मारक, लंदन 3. दीक्षा भूमि, नागपुर 4. चैत्य भूमि, दादर, मुम्बई 5. डॉ0 अम्बेडकर स्मारक अलीपुर रोड, दिल्ली के रूप में विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त कई सौ करोड़ की लागत से बना अम्बेडकर सेन्टर की सीापना सरकार द्वारा की गई है। जिसका शिलान्यास और फिर लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया।

स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने पर जिसमें मुख्यतः अन्य सरकारें रही अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति में ज्यादातर जगहों पर स्थिति में वांछित सुधार नहीं आया। इतने वर्षों बाद भी बाबा साहब की उम्मीदें पूरी न हो सकी थीं। वर्तमान सरकार की योजनाओं के पहले दलित समाज में बुनियादी चीजें जैसे–बिजली कलेक्शन, पानी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, छोटा सा घर, शौचालय, जीवन बीमा उपलब्ध नहीं हो पाई। इस कमी को श्री नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार ने पहली बार पूरा करने का काम किया है। आज मुद्रा योजना के तहत 60प्रतिशत लाभार्थी वंचित एवं आदिवासी समाज के लोग हैं। अब तक इस योजना के तहत लगभग पौने दस करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं एवं बिना गारन्टी 4 लाख करोड़ धनराशि का लोन दिया जा चुका है। स्वच्छ भारत योजना के तहत ज्यादातर अनुसूचित दलित–गरीब परिवारों के घरों में बनवाए गये हैं।

आजादी के 68 साल बीतने के बाद भी भारत के करीब 18 हजार गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, वहाँ अंधेरा पसरा था। इन गांव में एक बड़ी संख्या अनुसूचित, पिछड़े लोगों की भी रहती हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने समय सीमा के भीतर 1000 दिनों में ही इन गांवों में बिजली पहुंचाई।

प्रधानमंत्री जी ने **ग्राम स्वराज अभियान** शोषित, अनुसूचित, वंचित एवं इसमें भी विशेष रूप से महिलाओं को ताकत देने के लिए प्रारम्भ किया। मोदी सरकार आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार बनी है, जिसका 4 वर्षों को बजट ग्रामोन्मुखी है, गाँवों में जहाँ एक बड़ी संख्या में अनुसूचित आदिवासी रहते हैं। 2014–2018 के बजट पूरी तरह गाँव के अनुसूचित और गरीब किसानों को समर्पित है। पहली बार ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों के अनुदान में लगभग 200 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई।

23 सितम्बर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छततीसगढ़ से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरूआत की । इससे अभी गरीब पात्र व्यक्ति को 5 लाख प्रतिवर्ष तक का इलाज का बीमा मुफ्त मिलेगा।

इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को मिलेगा। उज्जवला योजना के तहत पहली बार सरकार की ओर से गैस चूल्हा और साथ में रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराया गया है।

गाँव की खुशहाली और अनुसूचित महिलाओं की खुशहाली का जो सपना महात्मा गाँधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो देखा था उसे पहली बार नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया है। भारत में पहली बार 5 करोड़ गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली हैं जिसमें बड़ी संख्या अनुसूचित समाज की महिलाओं की है।

मोदी जी द्वारा नए भारत के निर्माण का संकल्प बाबा साहब के स्वतंत्रता के तीन आधारों राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता में सामंजस्य सीापित कर नए भारत का निर्माण करना है जो बाबा साहब के सपनों का सम्राट अशोक जैसा धर्म सापेक्ष पंथ निरपेक्ष धर्मी समाज होगा।

- **शिक्षित बनो**– अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को देश में पढ़ने हेतु 10 लाख रूपये और विदेश में पढ़ने हेतु बिना किसी गारन्टर के 20 लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण देने का निर्णय किया गया।
- **चिकित्सा सम्बन्धी आर्थिक सहायता** – 1 लाख वार्षिक आय तक के अनुसूचित समाज के लोगों के लिए हृदय रोग, किडनी सम्बन्धी जैसे गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए 3 लाख रूपये तक की सहायता राशि का केन्द्र सरकार की ओर से प्रावधान है।
- **स्टैंड अप इंडिया**– योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवाओं की उद्यमी बनाने का काम किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश में श्री योगी अदित्यनाथ, मा0 मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, जन जाति, गरीबों, पिछड़ों असहायों हेतु कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ तथा गैस कनेक्शन, वरिष्ठ नागरिक सुविधा, शौचालय निर्माण एवं बैंक खाता खुलवाने की सुविधाओं को सर्व सुलभ कराया गया। ■

भारतीयता ही राष्ट्रीयत्व है।

भारतीयकरण' का अर्थ है– जीवन के विविध क्षेत्रों में भारतीयता का पुनःप्रतिष्ठा। **'भारतीयता'** शब्द 'भारतीय' विशेषण में **'ता'** प्रत्यय लगाकर बनाया गया है जो संज्ञा (भाववाचक संज्ञा) रूप में परिणत हो जाता है। भारतीय का अर्थ है – भारत से सम्बन्धित। भारतीयता से तात्पर्य उस विचार या भाव से है जिसमें भारत से जुड़ने का बोध होता हो या भारतीय तत्वों की झलक हो या जो भारतीय संस्कृति से संबंधित हो। भारतीयता का प्रयोग राष्ट्रीयता को व्यक्त करने के लिए भी होता है। भारतीयता के अनिवार्य तत्त्व हैं – भारतीय भूमि, जन, संप्रभुता, भाषा एवं संस्कृति। इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुचिता (आन्तरिक व बाह्य शुचिता) तथा सतत सात्विकता पूर्ण आनन्दमयता भी भारतीयता के अनिवार्य तत्त्व हैं। भारतीय जीवन मूल्यों से निष्ठापूर्वक जीना तथा उनकी सतत रक्षा ही सच्ची भारतीयता की कसौटी है। संयम, अनाक्रमण, सहिष्णुता, त्याग, औदार्य (उदारता), रचनात्मकता, सह–अस्तित्व, बन्धुत्व आदि प्रमुख भारतीय जीवन मूल्य हैं। भारतीयकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत महान प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा की जाती है। भारतीयकरण एक पुनःजगरण आन्दोलन है। यह आन्दोलन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में स्वदेशी पर अत्यधिक बल देता है। यह आन्दोलन भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित करने में कार्यरत है। यह आंदोलन मानवतावाद तथा भारतीय राष्ट्रीयतावाद पर बल देता है । यह आन्दोलन हिन्दी, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं की रक्षा करता है ।

भारतीयता से संबंधित सुभाषित व सूक्तियाँ संपादित करें

''भारत जब तक जग में होगा, भारतीयता तब तक होगी।''

''भारतीयता आध्यात्मिकता की तरंगों से ओत प्रोत है।'' – स्वामी विवेकानन्द

"भारतीयता का प्राण धर्म है, इसकी आस्था धर्म है और इसका भाव धर्म है।'' – महर्षि अरविंद

''भारतीयता होगी जब तक, जग होगा निरोगी तब तक।'' – बलदेव प्रसाद मिश्र

''सामाजिक, नैतिक तथा कलात्मक क्षेत्रों को भारतीयता तत्त्व दर्शनपरक सत्य और मूल्य प्रदान करती है।'' – राधा कमल मुखर्जी

भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति में मन में 'भारतीय' होने का भाव जितना अधिक होगा वे अपना भला बुरा भारत की उन्नति में देखेंगे। उनकी किसी गतिविधि से भारत का अहित होगा तो वे नहीं करेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपने आप को भारत का एक अंश, भारत माता का पुत्र माने। ऐसी स्थिति आने पर कोई भी राजनेता जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर देश को नहीं बांट सकेगा।

भारतीयता की प्रकृति

शिक्षा में भारतीयता

मानव जीवन की गुणवत्ता के संवर्द्धन तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा एक मूलभूत तत्त्व है। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि पूंजीगत एवं प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में मानवीय संसाधन प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास के चरित्र तथा गति को अधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास के निष्क्रिय तत्त्व हैं जबकि मानवीय संसाधन एक सक्रिय तत्त्व है। मानवीय संसाधन ही पूंजी का संचय करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संगठनों का निर्माण करते हैं तथा राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस तरह से जो राष्ट्र अपने नागरिकों में निपुणताओं तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करने तथा उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं वे कुछ भी विकास करने में सफल नहीं हो सकते।

विश्व बैंक रिपोर्ट 2007 में कहा गया है कि जो विकासशील देश अपनी युवा शक्ति (12–24 वर्ष) की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि पर विनियोग करते हैं, वहां अच्छी विकास की दर तथा घटती निर्धनता प्राप्त की जा सकती है।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन, शिक्षा आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। उत्पादकता एवं औद्योगिक किस्म को बढ़ाने, सूचना तंत्र तथा जैविक तकनीक क्षेत्र को गति देने, विनिर्मित एवं सेवा निर्यात क्षेत्र के उत्तेजित विस्तार करने, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने, घरेलू स्थिरता तथा शासन की गुणवत्ता के लिए सभी स्तरों पर जीवन में स्वदेशी स्वावलम्बन स्वभाषा, स्वसंस्कृति के रूप में जीवनचर्या का विकास ही विश्व में भारतीयता को सम्मान दिलायेगा। ■

स्वतंत्रता सेनानी राजा देवी बक्स सिंह

स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में हम अपने पूर्वजों के पौरूषता को याद कर रहे हैं ऐसे ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी फूट रही थी, तभी गोंडा व उससे सटे लखनऊ में भी विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी थी। लखनऊ की बेगम हजरत महल अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अवध क्रांति का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने मदद के लिए गोंडा के महाराजा देवी बक्स सिंह को पत्र भेजा जिस पर गोंडा के महाराजा लखनऊ की बेगम की मदद करने घाघरा पार पहुंचे थे।

गोंडा के राजा की जिम्मेदारी संभालने के बाद राजा देवी बख्श सिंह की शोहरत अवध के नवाब तक पहुंची। एक बार वे अवध के दरबार में बैठे थे, तभी वहां एक घोड़ा लाया गया। उस पर बैठने का कोई साहस नहीं कर पा रहा था। देवी बख्श सिंह ने दौड़कर घोड़े का लगाम पकड़ा और इतनी जोर से उसे डांटा कि पूरा दरबार कांप उठा। फिर वह घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हो गए। उस घोड़े को वह लखनऊ की सड़कों पर दौड़ाते रहे जब वापस दरबार पहुंचें तो घोड़े के मुंह से फेना बह रहा था। यह दृश्य देख बेगम हजरत–महल ने देवी बख्श सिंह को बुलाया और बेटा कहकर उन्हें सीने से लगा लिया। देवी बख्श सिंह ने भी उन्हें मां शब्द से संबोधित किया।

5 जुलाई 1857 को जब बेगम की शाही सेना के कैप्टन गजाधर पांडेय अनुरोध पत्र लेकर राजा के पास आए थे। यह पत्र बहुत ही मार्मिक था। जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अन्याय पूर्वक छीने गए राज्य, अवध के अवयस्क उत्तराधिकारी व बेघर की गई एक महिला को उसका हक दिलाने के लिए अन्यायी के विरुद्ध कमान संभालने का आग्रह किया था। जिस पर यहां से गोंडा के राजा ने अपनी सेना के साथ पहुंचकर उनका साथ दिया।

राजा देवी बख्श सिंह गोंडा–बहराइच के प्रधान नाजिम तो थे ही उन्हें बस्ती और बाराबंकी के भी आठ रजवाड़ों को मिलाकर कुल 30 रजवाड़ों के नायक के रूप में क्रांति का संचालन संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। फरवरी 1856 में ब्रिटिश राज्य में अवध का विलय करने के बाद जब कर्नल ब्वायलू यहां पर तैनात होकर आए तो उन्होंने राजा देवी बख्श सिंह के पास मिलने के लिए बुलावा भेजा किंतु वे आने को तैयार नहीं हुए। ब्रिटिश अमलदारी में हुए सरसरी बंदोबस्त में गोंडा के राजा के 400 गांवों में से तीस गांव कम कर दिए गए थे।

बेगम हजरत महल के आमंत्रण पर गोंडा के राजा अपनी सेना के साथ लखनऊ गए थे। जिसमें करीब तीन हजार सैनिक थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। यहां पर अंग्रेजों से हुए कई मुकाबलों के बाद 16 मार्च 1958 को बेगम ने चौलक्खी कोठी छोड़ दी। इसके बाद वह जहां भी ठहरीं, अंग्रेजों ने वहां पर उनका पीछा किया।

लखनऊ व चौकाघाट पर लड़ाई के बाद गोंडा राजा ने बेलवा के समीप अपना कैंप बनाया। यहां पर उन्होंने दो तोपों व 800 सैनिकों के साथ बेलवा को अपने कब्जे में कर लिया। हर मोड़ पर अंग्रेजों से मुकाबला होता रहा। ऐसे में नवंबर के प्रथम सप्ताह में गोंडा क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया।

सत्तावन की क्रांति का आरंभ भले ही सिपाही विद्रोह से हुआ था लेकिन इसने जनक्रांति का रूप ले लिया था। कई मोर्चों पर युद्ध होता रहा। लेकिन फैजाबाद से आ रही अंग्रेजी सेना का राजा देवी बख्श सिंह से लमती लोलपुर में आमना सामना हुआ। 15 दिनों तक यहां पर मोर्चा चला। बाद में गुपचुप तरीके से अंग्रेजी सेना घाघरा के इस पार उतर आई। लमती में दोनों के बीच युद्ध हुआ। यहां से राजा को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने नेपाल में जाकर शरण ली। वह वहां पर दांग घाटी के देवखुर नामक स्थान पर ठहरे थे। यही नहीं राजा देवी बख्श सिंह के पास समर्पण के भी कई प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया। वहीं पर उनकी मृत्यु की बात बताई जा रही है। राजा देवी बख्श सिंह को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। आज भी उनकी ड्योढ़ी पर ताजिया झुका दी जाती है।

महाराजा देवी बक्स सिंह के देशभक्ति के जुनून से प्रभावित होकर शहर से सटे पांच गांवों के युवा दुश्मन से लोहा लेने महाराजा की सेना के साथ निकल लेते थे। शहर से सटे केशवपुर पहड़वा, दत्तनगर विसेन, रुद्रपुरविसेन, जगदीशपुर तथा इमरती विसेन के लड़ाके युवा महाराजा देवी बक्स सिंह की सेना के साथ दुश्मन से लोहा लेने निकल पड़ते थे। माना जाता है कि बेगम हजरत महल की मदद के लिए जब महाराज लखनऊ कूच कर रहे थे तो उनके साथ इन पांच गांवों के सैकड़ों लड़ाके भी निकल पड़े थे। आजादी के इन दीवानों को कोटिशः नमन्। ■

केन्द्र सरकार की उपलब्धियां आर्थिक समीक्षा 2021–22

भारतीय अर्थव्यवस्था की 2021–22 में 92 प्रतिशत की भारी वृद्धि

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021–22 प्रस्तुत किया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021–22 में 9.2 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी। इसमें 2022–23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0–8.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2021–22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर संभावित है। औद्योगिक क्षेत्र में 2020–21 के दौरान 7 प्रतिशत की विकास दर तेजी से बढ़कर 2021–22 में 11.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 2021–22 में 8.2 प्रतिशत रहेगी।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। आर्थिक समीक्षा 2021–22 की मुख्य बातें निम्न हैं:

अर्थ व्यवस्था की स्थिति

- 2020–21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021–22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3 प्रतिशत (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) बढ़ने का अनुमान है।
- 2022–23 में जीडीपी की विकास दर 8–8.5 प्रतिशत रह सकती है।
- आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है।
- 2022–23 के लिए यह अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की क्रमशः 8.7 और 7.5 प्रतिशत रियल टर्म जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है।
- आईएमएफ के ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021–22 और 2022–23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9 प्रतिशत और 2023–24 में 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिससे भारत अगले तीन साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।
- 2021–22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9 प्रतिशत; उद्योग के 11.8 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- राजकोषीय मजबूती

31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है

- 2021–22 बजट अनुमान (2020–21 के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में) 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल–नवम्बर, 2021) 67.2 प्रतिशत तक बढ़ गईं।
- सालाना आधार पर अप्रैल–नवम्बर, 2021 के दौरान सकल कर–राजस्व में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019–20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है।
- अप्रैल–नवम्बर, 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बाह्य क्षेत्र

- भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज्यादा हो गया।
- 2021–22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसम्बर, 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।
- नवम्बर, 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था।

मौद्रिक प्रबंधन

- प्रणाली में तरलता अधिशेष रही।
- 2021–22 में रेपो दर 4 प्रतिशत पर बनी रही।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने और अधिक तरलता प्रदान करने के लिए जी–सेक अधिग्रहण कार्यक्रम तथा सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष

- अप्रैल–नवंबर, 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से 89,066 करोड़ रुपये उगाहे गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है।
- 18 अक्टूबर, 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी 61,766 तथा 18,477 की ऊंचाई पर पहुंचे।
- प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल–दिसंबर, 2021 में समकक्ष बाजारों से अच्छा प्रदर्शन किया।

मूल्य तथा मुद्रास्फीति

- औसत शीर्ष सीपीआई–संयुक्त मुद्रास्फीति 2021–22 (अप्रैल–दिसंबर) में सुधरकर 5.2 प्रतिशत हुई, जबकि

2020–21 की इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी।

- खुदरा स्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई।
- 2021–22 (अप्रैल से दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी।

सतत विकास तथ जलवायु परिवर्तन

- भारत, विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है।
- 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा।
- 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24 प्रतिशत रहे, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2 प्रतिशत।
- गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति 2017 के 39 प्रतिशत से सुधरकर 2020 में 81 प्रतिशत हो गई।

कृषि तथा खाद्य प्रबंधन

- पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन (जीवीए) में महत्वपूर्ण 18.8 प्रतिशत (2021–22) की वृद्धि हुई, इस तरह 2020–21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021–22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- पशुपालन, डेयरी तथा मछलीपालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं।
- 2019–20 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ा रहा।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है।

उद्योग और बुनियादी ढांचा

- अप्रैल–नवम्बर, 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 17.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गया। यह अप्रैल–नवम्बर, 2020 में (–)15.3 प्रतिशत था।
- भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009–2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020–21 में 155,181 करोड़ रुपये हो गया और 2021–22 में इसे 215,058 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है।
- वर्ष 2020–21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है जो 2019–20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, इस प्रकार इसमें 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के शुभारंभ से लेनदेन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ–साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी।

सेवाएं

- जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021–22 की जुलाई–सितम्बर तिमाही में पूर्व–महामारी स्तर को पार कर लिया है।
- समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021–22 में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- अप्रैल–दिसम्बर, 2021 के दौरान रेल मालभाड़ा ने पूर्व–महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई मालभाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व–महामारी स्तरों तक पहुंच गये हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात में धीर–धीरे वृद्धि हो रही है जो यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था।
- आईटी–बीपीएम सेवा राजस्व 2020–21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए।
- भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप इकोसिस्टम बन गया है। नये मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप्स की संख्या 2021–22 में बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है जो 2016–17 में केवल 735 थी।
- 44 भारतीय स्टार्ट–अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्ट–अप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं।

सामाजिक बुनियादी ढ़ांचा और रोजगार

- अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020–21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व–महामारी स्तर पर आ गए हैं।
- मार्च, 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएफएलएस) आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गये हैं।
- सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केन्द्र और राज्यों का व्यय जो 2014–15 में 6.2 प्रतिशत था; 2021–22 (बजट अनुमान) में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया।
- जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले 'हर घर जल' जिले बन गए हैं। ■

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

पं. दीनदयाल उपाध्याय

आदेवमातृका कृषि

सिंचाई की योग्य व्यवस्था करना भारतीय शासन का सदैव से ध्येय रहा है। कृषि को आदेवमातृका बनाना शास्त्रों आदेश है। स्वातंत्र्योत्तर काल में यद्यपि बड़े–बड़े बांधों के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं, फिर भी अधिकांश कृषि इंद्रदेव की कृपा पर ही निर्भर है। छोटी योजनाओं की ओर दुर्लक्ष्य हुआ है। पुराने कुएं, तालाब, पोखरे आदि मरम्मत के अभाव में बेकार हो गए हैं।

सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के लिए छोटे–छोटे सिंचाई के साधन ही उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजी–प्रधान हैं। देश के अनेक भू–भागों में भूमि और जल–तल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होता है, जिससे भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकाएं हैं। विद्यमान योजनाओं को छोड़कर आगे सामान्यतया छोटी योजनाएं ही हाथ में लेनी चाहिए। बड़ी योजनाओं में लगी पूंजी की शीघ्र वसूली की चिंता में सिंचाई एवं अन्य करों की दरें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसान उन्हें दुर्वह समझकर सिंचाई के साधनों का उपयोग ही न करें। छोटी योजनाओं में नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

भूधृति

कृषि उत्पादन का संबंध कृषक से भी होता है। खेत और खेतिहर इन दोनों का एक अविभाज्य संबंध है। भूमि में सुधार करने तथा अधिकाधिक श्रम से अधिकतम उत्पादन करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान को इस बात का विश्वास हो कि वह भूमि से हटाया नहीं जाएगा तथा पैदा की हुई फसल का अधिकांश भाग उसका अपना ही होगा। विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से भारत की भूमि व्यवस्था में बहुत से मध्यस्थों का समावेश हो गया है। जमींदार और जागीरदार अब समाप्त कर दिए गए हैं, किंतु रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, जो स्वयं खेती नहीं करते, बल्कि दूसरों को पट्टे पर देकर उनसे फसल का निश्चित भाग लेते रहते हैं। कानून में वे कृषक हैं और कृषि के नाम पर मिलनेवाली सुविधाएं उन्हें ही प्राप्त होती हैं। फलतः वास्तविक कृषक निर्धन एवं सुविधाहीन बना हुआ है। कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि वास्तविक किसान को भूमि का मालिक बनाया जाए। कुछ राज्यों में, जहां इस प्रकार के क़ानून बने हैं, उनका ठीक–ठीक पालन नहीं हुआ। गैर–कानूनी, बेदखली या मरती से खेत छोड़ने के मामले बहुत ज्यादा है। आवश्यकता है कि काग़ज़ों में सुधार हो तथा कानून की भावना के अनुसार उसका पालन हो।

जोतने वाले की भूमि

व्याख्याकृ'जोतनेवाले की भूमि' का यह अर्थ कदापि नहीं कि अपनी मेहनत को छोड़कर किसान किसी दूसरे की सेवाओं से लाभ नहीं उठा सकता। उसे आवश्यकतानुसार मजदूर रख सकने का अधिकार होना चाहिए, अन्यथा खेती चौपट हो जाएगी। 'जोतनेवाले' का साधारण अर्थ यही हो सकता है कि वह खेती के हानि–लाभ के लिए उत्तरदायी हो, उसमें पूंजी लगाता हो, वहां परिश्रम करता हो तथा उसकी देखभाल करता हो।

ऐसी अवस्थाएं भी हो सकती हैं, जब किसी कारणवश किसान एक या दो वर्ष के लिए खेती न कर सकता हो। यदि उस अवस्था में वह अपनी ज़मीन दूसरों को कुछ समय के लिए खेती करने के लिए नहीं दे सकेगा तो वह या तो खेत को बिना बोए हुए छोड़ देगा या केवल कागजी कार्रवाई के लिए उस पर खेती करेगा। इसका परिणाम कृषि उत्पादन के गिरने के रूप में होगा। अतः हमें कुछ अपवाद अवश्य करने होंगे। अवयस्कों, विधवाओं, अपंगों तथा फ़ौज के लोगों को भी इस नियम से मुक्त रखना होगा।

इसी प्रकार अलाभकर जोत वाले किसानों को अपना खेत

पट्टे पर देने और लेने का अधिकार होना चाहिए।

अधिकतम जोत

सघन खेती की अनिवार्यता के कारण हमें एक ओर आर्थिक जोतों की व्यवस्था करनी होगी तथा दूसरी ओर जोत की अधिकतम मर्यादाएं भी बांधनी होंगी।

कृषि स्वामित्व

सहकारी या सामुदायिक खेती भारत के भूमि–जन अनुपात, प्रजातंत्रीय पद्धति, बेकारी का निवारण, प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन, कृषि में मानकों के निर्धारण की असंभवनीयता, किसान का भूमि–प्रेम एवं हमारे जीवन–मूल्य, इन सभी दृष्टियों से हमारे लिए अनुपयुक्त है। कृषक स्वामित्व ही भूमि व्यवस्था का आधार होना चाहिए।

चकबंदी

भूमि का अंतर्विभाजन एवं अपखंडन भी भारतीय कृषि की एक समस्या है। इसे चकबंदी द्वारा रोकने के प्रयास किए गए हैं।

जिन तरीक़ों और क़ानूनों के अंतर्गत चकबंदी की जा रही है, उनमें पक्षपात एवं भेदभाव के लिए बहुत गुंजाइश है। गांव का मास्टर प्लान बनाकर चकबंदी करनी चाहिए। जिनके चक छोटे हैं, उन्हें भूमि देते समय यह ध्यान रखा जाए कि वे उन्हें लाभकर बना सकें।

आर्थिक जोत से नीचे अंतर्विभाजन और अपखंडन पर रोक लगा दी जाए।

सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के लिए छोटे-छोटे सिंचाई के साधन ही उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजी-प्रधान हैं। देश के अनेक भू-भागों में भूमि और जल-तल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होता है, जिससे भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकाएं हैं

खेतिहर मज़दूर

कृषि में खेतिहर मजदूर का सहयोग सदैव आवश्यक रहेगा। उसको पूरी मजदूरी, वर्ष भर काम तथा ग्रामवासियों को मिलनेवाली सभी सुविधाएं मिल सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु गांवों में सहायक उद्योगों की स्थापना आवश्यक है।

गोवंश की अवध्यता

गोवंश के प्रति भारतीय जनता की भावनाओं का समादर करने तथा उसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर अत्यधिक बल देना चाहिए तथा गोवंश हत्या पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। मिश्रित कृषि भारत के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

विपणन

उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों के साथ ही कृषि माल के विपणन एवं ऋण की व्यवस्था भी करनी होगी। अभी तक गांव का साहूकार कुछ अंशों में ये कार्य करता है। किंतु बाजारों की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण किसान को कभी उचित दाम नहीं मिल पाया है। कच्चे माल के कम दामों के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही मूलतः दोषी है। इसमें कच्चे माल और पक्के माल के मूल्यों के बीच कोई तालमेल नहीं। अतः किसान के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक है कि गांवों में कोठार एवं गोदाम बनाए जाएं, जिससे किसान को अपनी फसल की साख पर योग्य ऋण प्राप्त हो जाएं। सहकारी समितियां यह काम भली–भांति कर सकती हैं। कृषि बीमा योजना भी उपयोगी सिद्ध होगी।

वन

वन देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं। उनका प्रभाव देश की जलवायु एवं वर्षा पर भी पड़ता है। उनका ह्रास रोकने, संरक्षण एवं रोपण के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वन और वनवासी दोनों ही पिछले अनेक वर्षों से बुरी तरह शोषण के शिकार हुए हैं। वनवासी को खेती के लिए भूमि देना तथा वनों से आजीविका चलाने की सुविधा पुनः देना आवश्यक है।

उद्योग नीति

देश के औद्योगीकरण की अपरिहार्यता निर्विवाद है, किंतु उसकी गति कितनी और स्वरूप कैसा हो, यह मतभेद का विषय है। सामान्यतः पश्चिम के औद्योगिक ढांचे को ही एकमेव ढांचा मानकर उसे जल्दी–से–जल्दी देश में लाने की आतुरता दिखती है। विदेशी पूंजी के सहयोग ने इस निर्णय को और भी प्रभावित किया है। अभी तक इस प्रकार का जो औद्योगीकरण हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई है, किंतु दूसरी और पुराने उद्योग नष्ट होकर निरुद्योगीकरण एवं विपूंजीकरण हुआ है, बेकारी बढ़ी है, विदेशों पर निर्भरता तथा विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है, केंद्रीयकरण तथा आर्थिक विषमताएं अधिक हुई हैं तथा तेजी से होनेवाले नगरीकरण एवं अपने घर और गांव से दूर बड़े–बड़े शहरों में समाज–संबंध–विहीन जनसमुदाय के केंद्रीकरण से अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। हम इन समस्याओं को औद्योगीकरण के स्वाभाविक परिणाम कहकर नहीं टाल सकते। ■

जयन्ती विशेष

समरसता के संत शिरोमणि 'रविदास'

संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा 1976 ई0 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के सीर गोबर्धन गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोष दास था। उनके दादा का नाम श्री कालुराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपती जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोनाजी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी थे। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे।

उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिन्दुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे।संत रविदास जी बहुत ही दयालू और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे–सीधे लिखा कि **'रैदास जन्म के कारने होत न कोई नीच, नर कूं नीच कर डारि है, ओछे करम की नीच'** यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। उनके लगभग चालीस पद सिख धर्म के पवित्र धर्मग्रन्थ **'गुरूग्रंथ साहब'** में भी सम्मिलित किए गए हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि **''मन चंगा तो कठौती में गंगा''** इसको उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरूभाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने **'संतन में रविदास'** कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थीं। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ई0 में उन्होंने देह छोड़ दी थी।

वाराणसी में जयन्ती के अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली में योगी आदित्यनाथ जी ने माथाटेका। उन्होंने मंदिर में रविदास जी की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी को रविदास जयंती की बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार यहां के विकास काम के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन की सरकार उनकी पावन जन्मस्थली के समग्र विकास हेतु पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है।

इसके बाद उन्होंने लिखा कि यह हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत रविदास जी की जन्मस्थली **'सीर गोवर्धन'** यूपी0 की सांस्कृतिक नगरी काशी में हैं, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में **'सीर गोवर्धन'** के सुंदरीकरण और पर्यटन विकास हेतु राज्य सरकार समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी ने बताया कि लाखों जनआस्था की भूमि सीर गोवध्रन में आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इसके साथ ही संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृति में पार्क निर्माणाधीन है। ▪

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
फरवरी द्वितीय, लोक जागरण अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी